

उत्तरांचल शासन  
न्याय विभाग

संख्या 1501/XXXVI(1)/2006  
देहरादून : दिनांक १५ दिसम्बर, 2006

अधिसूचना  
प्रकीर्ण

मा0 मुख्यमंत्रियों एवं मा0 उच्च न्यायालयों के मा0 मुख्य न्यायाधीशों के दिनांक 11 मार्च, 2006 को आयोजित सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए श्री राज्यपाल निम्नलिखित दो समितियों के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

प्रथम स्तरीय कमेटी

- 1- मुख्य सचिव ।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय ।
- 3- न्याय सचिव, उत्तरांचल ।

द्वितीय स्तरीय कमेटी

- 1- मा0 मुख्यमंत्री ।
- 2- मा0 मुख्य न्यायाधीश, उत्तरांचल उच्च न्यायालय ।
- 3- मा0 न्यायमंत्री ।

आज्ञा से,

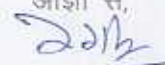
आलोक कुमार वर्मा  
अपर सचिव ।

संख्या 1501 (1)/XXXVI(1)/06-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिबन्धक, मा0 उत्तरांचल, उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 2- श्रीमती गार्गी मुकर्जी, संयुक्त सचिव (जे-11) विधि एवं न्याय मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, मान सिंह रोड, नई दिल्ली ।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
- 4- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की, हरिद्वार को इस अग्युक्ति के साथ प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने का कष्ट करें और अधिसूचना की 20 मुद्रित प्रतियां इस विभाग को भी भेजने का कष्ट करें ।
- 6- विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
- 7- एन.आई.सी./गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

  
(एम0 एम0 सेमवाल)  
अनु सचिव ।

प्रेषक,

एस० के० दास  
मुख्य सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
सिंचाई विभाग, उत्तरांचल,  
देहरादून।

सिंचाई विभाग

दिनांक. देहरादून. २१ दिसम्बर / ०६

विषय— सिंचाई विभाग के नियन्त्रणाधीन बीजापुर नहर पर स्थित ३  
घराटों को हिमालयन इन्वायरमैन्टल स्टडीज एण्ड कन्वर्जन  
और्गेनाइजेशन (हैस्को) को १० वर्ष हेतु लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश  
हुआ है कि जनपद देहरादून में बीजापुर नहर पर स्थित तीन घराट  
कमशः गढ़ी घराट न०-०१ एवं घराट न०-२ तथा डाकरा घराट न०-२,  
को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्र सं०  
४७००/सि०ख० /दिनांक ६-१२-०६ के द्वारा दिये गये प्रस्तावानुसार  
अस्थायी तौर पर प्रति वर्ष का शुल्क ५०००.०० रुपये प्रति घराट की दर  
से निर्धारित करते हुए लीज अवधि अगले १० वर्षों के लिए हिमालयन  
इन्वायरमैन्टल स्टडीज एण्ड कन्वर्जन और्गेनाइजेशन (हैस्को) को  
आवंटित करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ  
प्रदान की जाती है कि उक्त अवधि में घराटों के अनुरक्षण एवं मरम्मत  
कार्य, जलकर, विद्युत कर, एवं किसी भी प्रकार के अन्य कर आदि के  
देयकों का भुगतान (हैस्को) द्वारा स्वयं बहन किया जायेगा तथा <sup>लीज</sup>अवधि  
समाप्त होने पर घराटों की लीज समाप्त होने वाली तिथि को यथास्थिति  
में ही सिंचाई विभाग को वापस करना होगा



## शर्तें

- 1- घराट को लीज पर देने की अवधि 10 वर्ष होगी। लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त उसके नवीनीकरण/पुनः लीज दिये जाने पर मूल विभाग स्वतन्त्र होगा, और उसे लीज शर्तों एवं लीज शुल्क में वृद्धि / परिवर्तन किये जाने का अधिकार होगा।
- 2- प्रत्येक घराट को लीज अवधि में चलाना आवश्यक होगा एवं लीज की अवधि के मध्य यदि लीज धारक घराट को नहीं चलाता है या बन्द कर देता है, तो उसे लीज अवधि (10 वर्ष) तक का लीज शुल्क का भुगतान करना होगा। इस आशय का लिखित शपथ पत्र लीज धारक से ले लिया जाय।
- 3- लीज धारक द्वारा घराट किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, एवं लीज धारक बिना मूल विभाग की सहमति के घराट को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/ सोसाइटी/फर्म आदि को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- प्रत्येक घराट की लीज शुल्क रु0 5000/- प्रति वर्ष प्रति घराट होगी जो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून में प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।
- 5- घराट की लीज अवधि समाप्त होने के उपरान्त लीज धारक द्वारा घराट को यथास्थिति में सिंचाई विभाग को सौंपा जायेगा।
- 6- लीज धारक द्वारा घराट परिसर का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा और यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त शिकायत सही पायी जाती है तो लीज निरस्त कर दी जायेगी।
- 7- लीज धारक घराट परिसर को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने हेतु इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्द्धन करने के लिए स्वतन्त्र होगा, किन्तु इसकी ऐतिहासिक पहचान को बनाये रखना होगा, तथा लीजधारक घराट परिसर को अधिक से अधिक उपयोगी एवं बहुउद्देशीय बना सकता है किन्तु इसके लिए मूल विभाग की सहमति लेनी आवश्यक होगी। लीज समाप्ति के पश्चात घराट, भूमि एवं उस पर किया गया निर्माण स्वतः ही मूल विभाग में निहित हो जायेगा। जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- 8- घराट के संचालन एवं उसे बहुउद्देशीय बनाये जाने के कारण पेयजल / सिंचाई में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने एवं पर्यावरण पर

(3)

विपरीत प्रभाव पड़ने पर लीज समाप्त करने का अधिकार मूल विभाग को होगा।

- 9- लीज शर्तों / प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर या किसी अन्य विभाग/जन समुदाय के कारण विवाद होने पर जांचोपरांत लीज समाप्त कर दी जायेगी। परन्तु उस वर्ष का पूर्ण शुल्क लीज धारक से बसूल किया जायेगा।

उक्त आदेश राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस0 के0 दास  
मुख्य सचिव।

सं0 5703/11-2006-07(04)/04 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मा0 मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3- निजी सचिव, राज्य मंत्री, सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 6- जिलाधिकारी, देहरादून।
- ✓ 7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तरांचल देहरादून।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

21

(सुबईन)

अपर सचिव।



प्रेषक,

सचिव,  
औद्योगिक विकास,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,  
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग

देहरादून : दिनांक 20 दिसम्बर, 2006

**विषय :-** मैगा प्रोजेक्ट्स हेतु अधिसूचित भूमि के विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या-11/औ0वि0/07-उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004, शासनादेश संख्या-940/औ0वि0/07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक नीति-2003 के प्राविधानों के अनुरूप Mega Projects, जिनमें कुल पूंजी निवेश रु0 50 करोड़ से अधिक हो, की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं सुगमता से भूमि उपलब्ध कराने के दृष्टिगत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2003 में अधिसूचित भूमि को बृहत पूंजी निवेश की औद्योगिक इकाईयों द्वारा कय किये जाने पर Spot Zone औद्योगिक क्षेत्र के रूप में निम्नांकित दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/विनियमित किया जायेगा।

- 1- विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उतनी ही भूमि अधिसूचित/विनियमित की जायेगी, जितनी वास्तविक आवश्यकता Mega Projects के लिये हो।
- 2- Mega Projects का आशय ऐसे बृहत पूंजी निवेश के उद्योग से होगा, जिसमें कुल अचल पूंजी निवेश रु0 50 करोड़ से अधिक हो।
- 3- विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों आदि से नियमतः स्वीकृति, अनुमति, अनुमोदन तथा अनापत्ति आदि, जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित हैं, वह सम्बन्धित प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।
- 4- शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु जी0आई0डी0सी0आर0-2005 में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों, नियमों तथा उपबन्धों के अनुरूप भू-उपयोग, भवन निर्माण, हरित पट्टी, सड़क तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लिये निर्धारित मानकों का पूर्णतः पालन करना होगा।
- 5- ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की देख-रेख तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व प्रवर्तक कम्पनी की होगी।
- 6- विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु इच्छुक औद्योगिक इकाई/कम्पनी/ उद्यमी, इस आशय का आवेदन पत्र स्थापित किये जाने वाले उद्योग की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्री-फिजिविलिटी रिपोर्ट, ले-आउट प्लान/की-प्लान, स्थलीय मानचित्र, सजरा मानचित्र, खसरा खतौनी, कम्पनी का मैमोरेण्डम आफ आर्टीकल एण्ड एशोसियेशन की प्रति, निदेशक मण्डल का रेजूलेशन तथा भू-स्वामियों से भूमि कय करने के सम्बन्ध में किये गये कय अनुबन्ध पत्र की प्रति सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत करेंगे, ताकि

तदोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार Mega Projects के लिये कय की जा रही/कय अनुबन्धित भूमि को विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनियमित/घोषित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- 7- विशेष औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन/घोषित किये जाने के लिये प्रक्रिया निर्धारित करने, समय-समय पर शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन तथा विहित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये निदेशक उद्योग, उत्तरांचल सक्षम प्राधिकारी होंगे।

भवदीय,

6/11/2014  
(संजीव चोपड़ा)  
सचिव।

पृ० सं० 387/उक्त/ तददिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 4- संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
- 5- आयुक्त, कुर्माऊ/गढ़वाल मण्डल।
- 6- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
- 7- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष समस्त उद्योग संघ, उत्तरांचल।
- 9- समस्त जिलाधिकारी।
- 10- प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
- 11- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तरांचल, देहरादून।
- 12- सचिव, उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
- 13- समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
- 14- NIC Uttaranchal : इस अनुरोध के साथ की अधिसूचना को वेबसाईट पर प्रसारित कर दें।
- 15- गार्ड फाइल हेतु।

6/11/2014  
(संजीव चोपड़ा)  
सचिव।



प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,  
प्रमुख रायिव  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त  
उत्तरांचल, काशीपुर।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 12 दिसम्बर, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सडक निर्माण योजना  
(जिला योजना) हेतु वित्तीय स्वीकृति हेतु

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-726/XIV-2/2006 दिनांक 28 नवम्बर, 2006 को अवकमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सडकों के निर्माण की योजना के निमित निर्धारित पैटर्न के अनुसार 50 प्रतिशत राजकीय अंश वहन करने की पूर्व व्यवस्था में आंशिक संशोधन करते हुए 75 प्रतिशत राजकीय अंश वहन करने के लिए संलग्न विवरण के अनुसार रुपये 70.00 लाख (रुपये सत्तर लाख मात्र) की अनुपूरक के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

1) उक्त योजनान्तर्गत पक्की की जाने वाली सडकों पर होने वाले 25 प्रतिशत का व्यय लाभान्वित संस्थाओं/समितियों द्वारा वहन किया जायेगा।

2) राज्यांश की स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी अनुपात में किया जाय, जिस अनुपात में संस्था/ समिति द्वारा मैचिंग ग्रांट की धनराशि उपलब्ध कराई जाय।

3) उपर्युक्त धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 की लक्ष्य पूर्ति, इस वर्ष का लक्ष्य योजना, क्षेत्र के कृषकों को उत्पादन में प्रति हैक्टेयर वर्षवार वृद्धि, चीनी मिल क्षेत्र में कुल कितनी सडक निर्मित होनी थी, इसमें से कितनी निमित हो गयी व कितनी निर्मित होनी शेष है, आदि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

4) स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य जनपदों में कदापि न किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाय। स्वीकृत धनराशि का आहरण 25 प्रतिशत संस्थानों को अंशदान प्रेषित तथा चीनी मिल क्षेत्र में सडक को चिन्हित कर उनके आगमन समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होने पर ही किया जाये।

5) इस संदर्भ में वित्त(लेखा अनुभाग-1) के पत्रांक-ए-1-674/दस-78 (वि०स०आ०)/अनुभाग-1 दिनांक 07.03.1998 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-23-दस-15(18)/63 दिनांक 17.01.1997 में निर्दिष्ट अनुदेशों तथा इसके संलग्नक नियमों को ध्यान में रखें तथा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। स्वीकृत अनुदान उन्हीं शर्तों पर दिया जायेगा जो वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 में अध्याय-16ए में दी गयी है।



6) इस योजना के अन्तर्गत पक्की की गयी सड़कों का रखरखाव का उत्तरदायित्व संबंधित गन्ना विकास परिषद/समिति जो यह अनुदान प्राप्त करेगी, का होगा।

7) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय तभी किया जाये जब सम्बन्धित योजना में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा परिव्यय अनुमोदित करा लिया जाए।

8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग कर स्थिति की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जाए।

9) स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/अपर सचिव (गन्ना विकास) उत्तरांचल शासन तथा महालेखाकार उत्तरांचल को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2- उक्त व्यय वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक अनुदान संख्या-17 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-00-108-वाणिज्यिक फसलें, 91-जिला योजना, 9102- अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयो के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या- 148/वित्त अनु0-4/2006, दिनांक 13.12.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(पी0सी0शर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या-742 (1)/XIV-2/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, देहरादून।
- 3- कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- सहायक गन्ना आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-4 उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 6- बजट राजकोषीय नियोजन संसाधन निदेशालय उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 7- नियोजन विभाग उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून।
- 9- निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन देहरादून।
- 10-अपर सचिव, गोपन, उत्तरांचल शासन।
- 10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनुसचिव।



शासनादेश संख्या- / 2006 / XIV-2 / 2006 दिनांक नवम्बर, 2006 का

सलग्नक

अनुदान संख्या-17

2401-फसल कृषि कर्म

108-वाणिज्यिक फसलें

91-जिला योजना

9102-अंशदायी आधार पर अन्तरग्रामीण सडक निर्माण योजना,

20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता

(धनराशि लाख रुपये)

क्र. सं.	कार्यक्रम	उधमसिंह नगर	नैनीताल	हरिद्वार	देहरादून	योग
1	अंशदायी आधार पर अन्तर ग्रामीण सडक निर्माण योजना	—	—	—	70	70
	योग-	—	—	—	70	70

(सत्तर लाख रुपये मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)  
अनु सचिव।